

स्टार्टअप की रीढ़ बना इनोवेशन : गोयल

टियर-2 और 3 शहरों में तेजी से बढ़ रही उद्यमिता
स्टार्टअप को पूंजी और संरचना में सहयोग



नयी दिल्ली, 16 जुलाई. केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार स्टार्टअप इकोसिस्टम को लगातार मजबूत कर रही है. उन्होंने कहा टियर-2 व टियर-3 शहरों के उद्यमियों को और अधिक सशक्त बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है.

उद्योग जगत के नेताओं, स्टार्टअप संस्थापकों, नीति निर्माताओं और अन्य महत्वपूर्ण हितधारकों ने भाग लिया. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इनोवेशन भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की रीढ़ है और रिसर्च एवं डेवलपमेंट (र&D) को बढ़ावा

देना और सहयोग को बढ़ाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है. उन्होंने कहा, विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामूहिक प्रयास बेहद जरूरी हैं. पीयूष गोयल ने डीप-टेक स्टार्टअप को लेकर रचनात्मक बातचीत की और

इस बीच, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय स्टार्टअप अवार्ड्स के पांचवें संस्करण के लिए आवेदन आमंत्रित कर दिए हैं. इस पुरस्कार में कृषि, स्वच्छ ऊर्जा, फिनेटेक, एयरोस्पेस, स्वास्थ्य, शिक्षा, साइबर सुरक्षा और एक्सिबिलिटी जैसे कई क्षेत्रों को शामिल किया गया है. हर संस्करण में नई श्रेणियां जोड़ी जाती हैं ताकि वर्तमान समय की चुनौतियों और समस्याओं को अनुरूप बदलाव लाया जा सके.

तीन साल में दोगुना होगा ताप विद्युत में निवेश

2028 तक 2.3 लाख करोड़ रुपये का निवेश संभावित : क्रिसिल



नयी दिल्ली, 16 जुलाई (वार्ता) अगले तीन साल में देश में ताप विद्युत क्षेत्र में निवेश दोगुना होकर 2.3 लाख करोड़ रुपये पर पहुंचने का अनुमान है. बाजार सलाह कंपनी क्रिसिल की बुधवार को जारी रिपोर्ट में कहा है कि देश की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए ताप विद्युत उत्पादन पर एक बार फिर फोकस बढ़ रहा है. इससे अगले तीन वित्त वर्षों में साल 2028 तक पहले के तीन साल की तुलना में इस क्षेत्र में निवेश दोगुना होकर 2.3 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच जायेगा.

मात्र सात-आठ प्रतिशत के करीब था जो अगले तीन साल में बढ़कर एक-तिहाई हो जाएगा. सरकार ने वित्त वर्ष 2031-32 तक ताप विद्युत क्षमता में 80 गीगावाट की बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा है. इनमें से कुल 60 गीगावाट की परियोजनाओं की या तो घोषणा की जा चुकी है या वे विकास के विभिन्न चरणों में हैं. इनमें निजी क्षेत्र की परियोजनाएं

लगभग 19 गीगावाट की हैं. क्रिसिल रेटिंग्स के डिप्टी चीफ रेटिंग ऑफिसर मनीष गुप्ता ने कहा कि साल 2028 तक ऊर्जा की मांग करीब 5.5 प्रतिशत की औसत दर से बढ़ते हुए लगभग 2,000 अरब यूनिट पर पहुंच जायेगी. मांग में होने वाली वृद्धि में से लगभग 70 प्रतिशत की पूर्ति नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों द्वारा की जाएगी.

विद्युत कारों की बिक्री में तेज़ वृद्धि की उम्मीद



नयी दिल्ली, 16 जुलाई. केयरएज सलाहकार संस्था की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में विद्युत कारों (ई-कारों) की बिक्री वित्त वर्ष 2028 तक 7 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी को पार कर सकती है, यदि दुर्लभ पृथ्वी खनिजों की आपूर्ति में कोई बाधा न आए.

वृद्धि संभव है. भारत में विद्युत वाहन बिक्री वित्त वर्ष 2021 में 5,000 इकाई से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 1.07 लाख इकाई तक पहुंच गई, जो 21 गुना वृद्धि है. अभी दोपहिया और तिपहिया वाहनों का वर्चस्व है, परंतु चारपहिया खंड भी सरकारी नीतियों और निजी निवेश के कारण तेजी से आगे बढ़ रहा है. सरकार का लक्ष्य है कि वित्त वर्ष 2030 तक विद्युत वाहनों की 30 प्रतिशत भागीदारी हो. तेज अपनाने और निर्माण उन्नत रसायन शास्त्र बैटरी के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना और प्रमुख खनिजों पर शुन्य सीमा शुल्क जैसी योजनाएं उत्पादन लागत को घटाएंगी.

शेयर बाजारों में लगातार दूसरे दिन तेजी

मुंबई, 16 जुलाई (वार्ता). विदेशों से मिले मिश्रित रुख के बीच बुधवार को घरेलू शेयर बाजार मामूली बढ़त में रहे. बीएसई का संसेक्स 63.57 अंक यानी 0.08 प्रतिशत की हल्की तेजी के साथ 82,634.48 अंक पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के निफ्टी में भी 16.25 अंक यानी 0.06 प्रतिशत की मामूली सुधार रहा और यह 25,212.05 अंक पर पहुंच गया. विदेशों में एशियाई बाजार गिरावट में बंद हुये जबकि यूरोपीय बाजारों में तेजी का रुख रहा. संसेक्स की 30 में आधी कंपनियों के शेयर लाल निशान में बंद हुए. लाभ में रहे शेयरों में महिंद्रा एंड महिंद्रा में दो प्रतिशत से अधिक की बढ़त देखी गयी.

भारत बनेगा सौर ऊर्जा नवाचार में अग्रणी

सरकार ने तय किया 1.27 लाख करोड़ का नवाचार बजट
आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा



नयी दिल्ली, 16 जुलाई.केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत अत्याधुनिक नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, ताकि भारत स्वच्छ ऊर्जा नवाचार के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश बन सके.

प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई की उन्नत सौर तकनीक टीम से आग्रह किया कि वे पेट्रोब्रैकडेट टैंडम सौर कोशिका को व्यावसायिक रूप से प्रदर्शित करें, जिसकी रूपांतरण क्षमता 29.8 प्रतिशत है और यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है.उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने हाल ही में अनुसंधान, विकास और नवाचार योजना को मंजूरी दी है, जिसके अंतर्गत अनुसंधान पर कुल व्यय का बजट 1.27 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है.

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पिछले 15 वर्षों में एनपीसीआई की 200 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की है, साथ ही उन्नत सौर तकनीक भारत परियोजना को पायलट निर्माण सुविधा के लिए लगभग 83 करोड़ रुपये का समर्थन भी प्रदान किया गया है. केंद्रीय मंत्री ने दोहराया कि मंत्रालय देश के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को नवाचार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने हेतु नीतिगत और आर्थिक सहायता जारी रखेगा.

नकली ट्रेडमार्क वाले उत्पाद बेचना बंद करें : दिल्ली हाईकोर्ट

अमेज़न, फ्लिपकार्ट समेत कई ई-कॉमर्स वेबसाइटों को नोटिस
बिना अनुमति ब्रांड नाम का प्रयोग उपभोक्ता को गुमराह करता है



नई दिल्ली, 16 जुलाई. दिल्ली हाईकोर्ट ने दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनियों अमेज़न और फ्लिपकार्ट सहित कई अन्य ई-कॉमर्स वेबसाइटों को रिलायंस और जियो ट्रेडमार्क का उल्लंघन करने वाले उत्पादों को नहीं बेचने का आदेश दिया है.

कोर्ट ने रिलायंस की दलीलों से सहमत जताते हुए कहा कि उपभोक्ता वस्तुओं की पहचान के लिए ग्राहक ब्रांड नाम और कंपनी-लोगो पर निर्भर करते हैं. ऐसी परिस्थितियों में, यदि उत्पादों के बीच किसी भी प्रकार का भ्रम है, तो इससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा हो सकता है.

उल्लंघन करने वाले सभी उत्पादों के निर्माण और उनके विज्ञापनों पर भी रोक लगाने का निर्देश दिया. दरअसल, कई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर रिलायंस और जियो के ट्रेडमार्क से मिलते-जुलते नामों और कंपनी-लोगो का इस्तेमाल करके उत्पाद बेचे जा रहे थे. रिलायंस और जियो ने तर्क दिया कि ये कंपनियां उनकी साख का फायदा उठाकर ग्राहकों के भरोसे से फिलवाड़ कर रही थीं. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिस भी उत्पाद को रिलायंस या जियो ने नहीं बनाया है, उसे उनके नाम से नहीं बेचा जा सकता.

सिंगापुर से पैसा भेजना होगा आसान

17 जुलाई से नया रिमिटेंस नेटवर्क प्रभावी
बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, पीएनबी समेत 13 बैंक जुड़े

पेमेंट्स लिमिटेड ने बुधवार को बताया कि नये बैंकों के माध्यम से सीमा पार भुगतान 17 जुलाई से प्रभावी हो जाएगा. सिंगापुर से भारत और भारत से सिंगापुर पैसा भेजने के लिए अब लोगों के पास ज्यादा विकल्प होंगे.जिन बैंकों को रिमिटेंस नेटवर्क से जोड़ा गया है उनमें बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इंडसइंड बैंक, कऋ वैश्य बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, साउथ इंडियन बैंक और यूको बैंक शामिल हैं.

जून में फार्मा मार्केट की 11.5 प्रतिशत छलांग

नयी दिल्ली, 16 जुलाई. भारतीय फार्मा मार्केट ने इस वर्ष जून में सालाना आधार पर 11.5 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की है. यह जानकारी बुधवार को जारी एक रिपोर्ट में दी गई. मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की मासिक रिपोर्ट के अनुसार, इसकी तुलना में, पिछले वर्ष जून में, आईपीएम में 7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी.

कारण एक्वेट थैरेपी में वृद्धि जून 2024 के 7 प्रतिशत और मई 2025 के 5 प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष जून में 11 प्रतिशत रही. जून में एंटी-इन्फेक्टिव दवाओं की वार्षिक वृद्धि दर में पिछले महीनों की तुलना में महत्वपूर्ण सुधार हुआ. रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 12 महीनों में आईपीएम की वृद्धि में 4.2 प्रतिशत मूल्य वृद्धि, उसके बाद 2.3 प्रतिशत नए लॉन्च वृद्धि और 1.5 प्रतिशत मात्रा वृद्धि का योगदान रहा.

रिपोर्ट में कहा गया है कि जून में कुल आईपीएम में एक्वेट सेगमेंट की हिस्सेदारी 60.8 प्रतिशत रही, जबकि सालाना आधार पर वृद्धि 6.8 प्रतिशत रही. इसके अलावा, रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जून में परेल्फे कंपनियों ने बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों से बेहतर प्रदर्शन किया.जून तक भारतीय दवा कंपनियों के पास आईपीएम में 84 प्रतिशत की ज्यादा हिस्सेदारी है, जबकि शेष बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास है. रिपोर्ट में कहा गया है कि जून 2025 में सालाना आधार पर भारतीय कंपनियों की वृद्धि दर 11.6 प्रतिशत रही, जबकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों की वृद्धि दर 11.2 प्रतिशत रही.

समाचार विशेष

शरद हुए एक्टिव, तय होगा पाटिल का भविष्य

शिंदे की लगेगी लॉटरी
मुंबई. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल के इस्तीफे की खबर के बीच शरद पवार एक्टिव हो गए हैं. पार्टी के प्रवक्ता और विधायक जितेंद्र आव्हाड ने जयंत पाटिल की खबर को कोरी अफवाह बताया. लेकिन इस बीच शरद पवार ने पार्टी की बैठक बुला ली है.



मंगलवार को एक बैठक करेगी. एनसीपी (एसपी) की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने अपने पद से इस्तीफा देने की खबरों के बीच यह भी अटकलें लगाई जा रही है कि पार्टी के विधान परिषद सदस्य शशिकांत शिंदे उनकी जगह ले सकते हैं. इधर शशिकांत शिंदे भी

इन खबरों से खुश नजर आए. उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें मौका दिया गया तो यह उनके लिए एक निर्णायक मोड़ होगा. एनसीपी के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता जितेंद्र आव्हाड ने शनिवार को एक बयान में पाटिल के इस्तीफे की खबरों को शरारतपूर्ण बताया.

2018 से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जयंत पाटिल

जयंत पाटिल 2018 से अविभाजित एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे. जुलाई 2023 में अजित पवार और अन्य विधायकों के विद्रोह तथा पार्टी के विभाजन के बाद पाटिल शरद पवार गुट में उसी पद पर बने रहे. दरअसल, एनसीपी के 26वें स्थापना दिवस पर 10 जून को जयंत पाटिल ने पार्टी प्रमुख शरद पवार की मौजूदगी में पद छोड़ने का संकेत दिया था.

ममता अभी से तैयारी में लग गईं

कोलकाता. बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चल रहा है. इसके बाद पश्चिम बंगाल की बारी है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा दिया है कि बिहार के बाद पश्चिम बंगाल और असम में गहन पुनरीक्षण होगा. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है. उसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में मतदाता सूची की सफाई का काम होगा. चुनाव आयोग ने सभी राज्यों को इसके लिए तैयार रहने को कहा है. चुनाव आयोग को अब सुप्रीम कोर्ट का भी साथ मिल गया है. बिहार में

पुनरीक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक नहीं लगाई. सिर्फ पश्चिम के दस्तावेज के तौर पर आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड और राशन कार्ड को रवीकार करने की सलाह दी. चुनाव आयोग ने अभी तक इनको मान्यता नहीं दी है. उसकी टीम इस पर विचार कर रही है.पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को अंदाजा हो गया है कि चुनाव आयोग किस तरह से काम कर रहा है. उनको यह भी समझ में आ गया है कि यह सिर्फ मतदाता सूची का पुनरीक्षण नहीं है, बल्कि नागरिकता जांचने का अभियान है.

बिहार में महागठबंधन का सीएम चेहरा कौन?



पटना. बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है. पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरेगे और राहुल गांधी से मुलाकात की. बैठक के बाद उन्होंने बयान दिया कि कांग्रेस के पास भी कई मुख्यमंत्री पद के योग्य चेहरे हैं, जिनमें उन्होंने राजेश राम और तारिक अनवर इनमें से हैं. राहुल गांधी की विचारधारा को बिहार के हर घर तक ले जाने की कोशिश करूंगा.

गई है. खासकर राजद खेमे में बेचैनी देखी जा रही है, जिसने पहले ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर रखा है. यह पहली बार था जब पप्पू यादव कांग्रेस की किसी बिहार चुनाव संबंधी रणनीतिक बैठक में शामिल हुए. बैठक में बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लवर और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम भी मौजूद थे. चर्चा आगामी चुनाव में गठबंधन की रणनीति को लेकर हुई. सूत्रों के मुताबिक, पप्पू यादव की राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरेगे से अलग से भी बातचीत हुई. बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस के पास मुख्यमंत्री पद के लिए कई योग्य चेहरे हैं. राजेश राम और तारिक अनवर इनमें से हैं. मैं राहुल गांधी की विचारधारा को बिहार के हर घर तक ले जाने की कोशिश करूंगा.

विशेष ज्यादा ताकतवर होगा भाजपा अध्यक्ष, नागपुर से आया संदेश



नई दिल्ली. भारतीय जनता पार्टी अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश में है, क्योंकि वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 में समाप्त हो रहा है. मीडिया में कई नामों को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं. लेकिन अभी तक नाम फाइनल नहीं हुआ है. वैसे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी

पाँच देशों की यात्रा से लौट आए हैं, इसलिए माना जा रहा है कि नए भाजपा अध्यक्ष पर जल्द ही मुहर लग सकती है. इस मौके पर जानते हैं कि क्या भाजपा अध्यक्ष पद के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कोई विचारधारा भी काम करेगी? क्या नए अध्यक्ष की नियुक्ति में संघ का ही पूर्ण योगदान होगा? क्या वाकई

घटेगी मोदी-शाह की पावर!

नया बीजेपी अध्यक्ष पीएम मोदी और अमित शाह से ज्यादा ताकतवर होगा? एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, भाजपा के अगले अध्यक्ष पद के लिए नामों की चर्चा के बीच, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से नागपुर से एक स्पष्ट संदेश आया है कि भाजपा का अगला अध्यक्ष सिर्फ एक रणनीतिकार नहीं, बल्कि वैचारिक रूप से मजबूत और संगठन से गहराई से जुड़ा हुआ होना चाहिए. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आरएसएस चाहता है कि अगला भाजपा अध्यक्ष युवा और ज़मीनी स्तर का हो. वह शाखाओं,

प्रचारकों और बुध स्तर के कार्यकर्ताओं से सीधा जुड़ा हो. उसकी वैचारिक स्पष्टता हो. समान नागरिक संहिता, जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों पर उसकी स्पष्ट सोच हो. संघ को नहीं पसंद ये काम आरएसएस की चिंता यह है कि जीत की चाह में भाजपा कई ऐसे लोगों को भी पार्टी में ले रही है, जिनका विरोध हो रहा है. पार्टी में बाहरी नेताओं (जो दूसरे दलों से आए हैं) और टेक्नोक्रेट्स का प्रभाव बढ़ रहा है, जो आरएसएस को पसंद नहीं है. वह चाहता है कि

नया अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति हो जो वैचारिक रूप से पार्टी की मूल विचारधारा को मजबूत करे. आरएसएस और भाजपा का रिश्ता आपसी सहमति और संतुलन पर आधारित है. मोदी की लोकप्रियता और शाह की रणनीति ने पिछले एक दशक में भाजपा को अभूतपूर्व सफलता दिलाई है. लेकिन 2024 कचुनाव नतीजों ने दिखा दिया कि अब सिर्फ मोदी की छवि ही जीत के लिए काफी नहीं है. आरएसएस का मानना है कि पार्टी को वैचारिक दृढ़ता और संगठनात्मक मजबूती पर ध्यान केंद्रित करना होगा.

क्या है आरएसएस की भूमिका?

आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक मार्गदर्शक है. यह अध्यक्ष के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन खुलकर हस्तक्षेप नहीं करता. इसके बजाय, यह भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से परामर्श करता है. आरएसएस चाहता है कि नया अध्यक्ष संगठन को स्वायत्तता दे और कार्यकर्ताओं की आवाज सुने. मोदी और शाह अभी भी भाजपा के सबसे बड़े चेहरे हैं. लेकिन आरएसएस का मानना है कि पार्टी को अब दूसरी पंक्ति का नेतृत्व तैयार करना होगा, खासकर इसलिए क्योंकि मोदी सितंबर 2025 में 75 वर्ष की हो जाएंगे.